



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—रूप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521]

No. 521] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 1981/ग्राहायण 3, 1903

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 1981/AGRAHAYANA 3, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

(ओद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1981

24 मई, 1982 सक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है छह मास की  
प्रबंधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फांस० 3/17/75-सी यू सीएस]

### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

#### ORDER

New Delhi, the 24th November 1981

S.O. 825(E) 18AA/IDRA/81.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 826(E)/18AA/IDRA/76, dated 25th November, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Pulaon Cotton Mills Limited, Pulgaon, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of the 24th November, 1981 and the Maharashtra State Textile Corporation was authorised to take over the management of the said Industrial undertaking;

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Maharashtra State Textile Corporation for a further period of six months upto the 24th May, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue

प्रत. केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1951 (1951 का 65) की वारा 18कक की उपधारा (2), द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेश देती है कि उक्त व्यवेष

to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 24th May, 1982.

[File No. 3/17/75-CUS]

का०आ० 826(ए)/18 च व/आई डी आर—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के बाइ (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उद्योग मंत्रालय (शौधोगिक विकास विभाग) के आदेश स० का०आ० 826(ए)/18 च व/आई डी आर. प/76, तारीख 23 दिसम्बर, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा दीर्घायन किया था कि उक्त आदेश के जारी होने वी नारीख से ठोक पूर्व प्रदूत सभी या किसी संविदा, सम्पत्ति, हस्तान्तरण पक्षों, करारों, घवेस्थापनों, पंचांगों स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों [महाराष्ट्र, सरकार द्वारा प्रत्याभूत स्पेट नकद प्रत्यय सीमा के अधीन परावेय रकम के विस्तार तक भारतीय स्टेट बैंक के प्रति दायित्वों को और नकद प्रत्यय लेखा (माधारण) में से मिल द्वारा निकाली गई रकमों को, जहां तक कि वे वर्तमान अस्तियों के प्रतिशत हैं, ठोकर] में प्रवर्तन, जिनका भैसं पुलगांव काटन मिलत लिमिटेड, पुलगांव नामक शौधोगिक उपकरण एक पक्षकार है या जो उक्त शौधोगिक उपकरण को लागू हो सकते हैं, ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निम्निकृत रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्धूत या उद्भूत सभी अधिकार विशेषाधिकार, वाध्यताएं, और धायित्व उक्त प्रवधि के लिए निम्निकृत रहेंगे;

और उक्त आदेश की प्रवधि समय-समय पर विस्तारित की जाती रही है, जिसमें से प्रत्यिम विस्तारण 24 नवम्बर, 1981 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए था :

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त प्रवधि की प्रवधि 24 मई, 1982 तक की आगामी प्रवधि तक (जिसमें यह तिथि भी शामिल है), के लिए और विस्तारित कर दी जानी चाहिए;

अतः भव केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के बाइ (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, उक्त आदेश की प्रवधि 24 मई, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए और विस्तारित करेंगी हैं।

[फा०सं० 3 (17)/75-सी यू एस]  
चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

No. S.O. 826 (E)/18FB/IDRA/81.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 826(E)/18FB/IDRA/76, dated the 23rd December, 1976 (hereinafter referred to as the said order) the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operations of all or any of the contracts, assurances of property agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said order (other than the liabilities to the State Bank of India to the extent of the amounts outstanding on the clean cash credit limit guaranteed by the Government of Maharashtra and the amounts drawn by the mill against the cash credit account (ordinary) to the extent these are covered in the current assets) to which the industrial undertaking known as Messrs Pulgaon Cotton Mills Limited, Pulgaon, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the duration of the said order was extended from time to time, the last of such extensions being upto and inclusive of 24th November, 1981;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said order should be extended for a further period upto and inclusive of 24th May, 1982;

Now, therefore, In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said order upto and inclusive of 24th May, 1982.

[F. No. 3(17)/75-CUS]  
C. K. MODI, Jt. Secy.